पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

प्रदीप श्रीवास्तव

बनाम

बिहार राज्य

2024 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 1133

11 सितंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

हेडनोट्स

वर्तमान अपील 28.01.2023 के दोषसिद्धि के फैसले और 09.02.2023 के सजा के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसे छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा पी.टीआर. सं. 14/2020 के संबंध में पारित किया गया है, जो तुरकौलिया (बंजरिया) थाना मामला सं. 850 of 2019 से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत और जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(1) के तहत ₹20,000/- के जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा दी है, जुर्माना न देने पर एक महीने का साधारण कारावास। इसके अलावा, दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत ₹10,000/- के जुर्माने के साथ पांच साल के साधारण कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया है, जुर्माना न देने पर पंद्रह (15) दिन का साधारण कारावास। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को ₹10,000/- के जुर्माने के साथ सात साल के कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना न देने पर, दोषी को एक महीने के साधारण कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया और यह भी आदेश दिया गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

मामला तुरकौलिया (बंजरिया) थाना मामला सं. 850 of 2019 से उत्पन्न हुआ, जिसे नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा शुरू किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता ने लगभग दस दिनों की कैद के दौरान उसकी बेटी का बार-बार बलात्कार किया। पीड़िता को कथित तौर पर 'छट्ठी माई' पर छोड़ दिया गया था। पीड़िता ने गवाही दी कि उसका अपहरण अपीलकर्ता सहित दो व्यक्तियों द्वारा किया गया था और उसे एक वन क्षेत्र में ले जाया गया था जहां कथित हमले हुए थे। उसने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के साथ किसी भी रोमांटिक संबंध से इनकार किया। 13 मई, 2022 को अपनी जांच के दौरान, उसने

अपीलकर्ता की पहचान अपने अपहरणकर्ता और हमलावर के रूप में की। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता की गवाही "उत्कृष्ट गुणवत्ता" की नहीं थी और उसमें विसंगतियां और विरोधाभास थे जो उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करते थे। बचाव पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को भी उजागर किया, जिसे पीड़िता के बरामद होने के 15 दिन बाद और घटना के 25 दिन बाद दर्ज किया गया था, जिससे दावों की सत्यता पर संदेह पैदा हुआ।

आगे यह तर्क दिया गया कि घटना के संबंध में पीड़िता का बयान उत्कृष्ट गुणवत्ता का नहीं है, और इसलिए, किसी और पुष्टि के अभाव में, दर्ज की गई दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल पीड़िता की गवाही पर दर्ज की जा सकती है, लेकिन यह भरोसेमंद, निर्दोष और उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 130 पर भरोसा किया और राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2012) 8 एससीसी 21 पर भी भरोसा किया। और राजाक मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2018) 9 एससीसी 248 में भी; जहां यह माना गया है कि रेडियोलॉजिकल जांच के आधार पर उम्र का निर्धारण सटीक नहीं माना जाना चाहिए और दोनों तरफ पर्याप्त मार्जिन की अनुमति दी जानी चाहिए।

सहायक लोक अभियोजक ने जोर देकर कहा कि इस तरह के मामलों में मामूली विरोधाभास सामान्य हैं और उन्हें पीड़िता के बयान को अमान्य नहीं करना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता की गवाही की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से हुई, जिसमें चिकित्सा परीक्षण भी शामिल है।

निर्णय,

इन सभी पृष्ठभूमियों पर चर्चा करने के बाद, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के अर्थ में पीड़िता को 'बच्चा' साबित नहीं कर सका और, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई दोषसिद्धि विश्वसनीय नहीं लग रही है, और इसलिए, अधिनियम के तहत उपलब्ध अनुमान, जैसा कि धारा 29 और 30 के तहत उपलब्ध है, वर्तमान मामले में कोई मायने नहीं रखता है। यह भी पाया गया कि पीड़िता की गवाही, हालांकि महत्वपूर्ण थी, लेकिन "उत्कृष्ट गवाह" के लिए आवश्यक कड़े मानकों को पूरा नहीं करती थी। उसके बयान में विसंगतियों, अपराध की रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण देरी के साथ,

अभियोजन पक्ष के बयान पर संदेह पैदा हुआ।

इसलिए, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है, तदनुसार, 28.01.2023 के दोषसिद्धि के दोषपूर्ण निर्णय और 09.02.2023 के सजा के आदेश, जिसे छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पाँक्सो अधिनियम, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा पी.टीआर. सं. 14/2020 के संबंध में पारित किया गया था, जो तुरकौलिया (बंजरिया) थाना मामला सं. 850 of 2019 से उत्पन्न हुआ था, को रद्द और निरस्त किया जाता है। नतीजतन, अपीलकर्ता, जिसका नाम प्रदीप श्रीवास्तव है, को विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

चूंकि अपीलकर्ता उपरोक्त मामले के संबंध में हिरासत में है, उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है। यदि कोई जुर्माना जमा किया गया है तो उसे तुरंत अपीलकर्ता को वापस कर दिया जाए। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले की एक प्रति के साथ ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स (टीसीआर) को बिना देरी के विद्वान ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दे।

अपील स्वीकार की गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री सुधीर कुमार सिंह; श्री प्रियेश कुमार

उत्तरदाता/ओं की ओर से: श्रीमती अनीता कुमारी सिंह

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सारंगधर उपाध्याय

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 1133

थाना मामला संख्या- 850 वर्ष-2019 थाना-तुर्कोलिया जिला-पूर्वी चंपारण से उद्भूत

=====

प्रदीप श्रीवास्तव पिता ललन श्रीवास्तव निवासी गाँव-चिलवानिया, थाना-तुर्कोलिया (बंजारिया),
जिला- पूर्वी चंपारण।

..... अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता /ओं के लिए	:	श्री सुधीर कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री प्रियेश कुमार, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, अपर. लोक अभियोजक

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक : 11-09-2024

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार सिंह और राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्रीमती अनीता कुमारी सिंह को सुना।

2. वर्तमान अपील ज्ञापन, तुर्कोलिया (बंजरिया) थाना मामला संख्या 850/2019 से उद्भूत पी.टीआर. संख्या 14/2020 के संबंध में, विद्वान छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक 28.01.2023 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 09.02.2023 को पारित सजा के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 20,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दस (10) वर्ष

के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जुर्माना अदा न करने पर एक माह की सरल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोषी को पाँक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत पाँच (5) साल की सरल कारावास की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतने का आदेश दिया जाता है, जुर्माना न चुकाने पर पंद्रह (15) दिन की सरल कारावास । इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध के लिए सात (7) साल की कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतने का दोषी ठहराया है, और जुर्माना न चुकाने पर दोषी को एक महीने की सरल कारावास भुगतने का आदेश दिया है, साथ ही, यह भी आदेश दिया गया है कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

3. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि पीड़िता के पिता (अ.सा.-2) की लिखित सूचना से पता चलता है, कि जब उनकी लगभग 12 वर्षीय नाबालिग बेटी 03.11.2019 को सुबह लगभग 4:00 बजे 'छठ घाट' जा रही थी, तो दो अभियुक्तों, प्रदीप श्रीवास्तव (अपीलकर्ता) और सह-अभियुक्त सुमन श्रीवास्तव ने उसे जबरन घसीटा और अपनी मोटरसाइकिल के बीच में बैठा लिया और अंबिका नगर की ओर ले गए। सूचक ने आरोप लगाया कि कुछ ग्रामीणों ने देखा कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने सूचक को घटना की सूचना दी, जिसके बाद सूचक ने अपने परिवार के साथ आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे पकड़े नहीं गए। सूचक ने बताया कि जब वह आरोपियों के घर पहुँचा और उनके पिता से मिला, तो उन्होंने उसे उसकी नाबालिग बेटी को लौटाने का आश्वासन दिया। सूचक ने आगे बताया कि उसने इस घटना के संबंध में संबंधित पुलिस थाने में कोई आवेदन नहीं दिया। उसने बताया कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को घटना के 8-10 दिन बाद 'छट्ठी माई' छोड़ गए। उसने आरोप लगाया कि आरोपी प्रदीप श्रीवास्तव (अपीलकर्ता) ने उसकी नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर दस दिनों तक उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और उसे जातिसूचक शब्द कहकर गालियाँ दीं और धमकी दी कि वह उसकी बेटी के साथ बनाई गई तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर देगा। उन्होंने आगे

बताया कि जब उनके बेटे ने फेसबुक पर सोशल मीडिया अकाउंट खोला, तो उसने पाया कि वे तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए गए थे। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई।

4. उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने तुरकौलिया (बंजरिया) थाना में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की। मामला संख्या 850/2019 भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366(ए), 376 और 34 के साथ लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4/8 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम की धारा 3(i)(आर)(डब्ल्यू) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र संख्या 21/2020 दिनांक 27.02.2020 प्रस्तुत किया और जिसके आधार पर, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 365 पाँक्सो अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित, के तहत संज्ञान लिया गया 18.03.2020 को, लेकिन जाँच के दौरान एकत्रित सामग्री के अवलोकन के बाद, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 365, 370, 376(3) के साथ-साथ पाँक्सो अधिनियम की धारा 4, 10 और 14, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम की धारा 3(i)(w) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(B) के तहत 09.09.2021 को आरोप तय किए गए।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को उपरोक्त आरोपों के बारे में समझाया, जिस पर उन्होंने "दोषी नहीं" होने का तर्क दिया और मुकदमे की मांग की।

6. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने नाबालिग पीड़िता सहित कुल सात (7) गवाहों से पूछताछ की, जो इस प्रकार हैं: -

अ.सा.-1 अर्थात्, x (पीड़िता)

अ.सा.-2 अर्थात्, उमेश पासवान (सूचक और पीड़िता का पिता)

अ.सा.-3 अर्थात्, मनोरमा देवी (पीड़िता की माँ)।

अ.सा.-4 अर्थात्, रमेश राम

अ.सा.-5 अर्थात्, डॉ. मनोज कुमार

अ.सा.-6 अर्थात्, संतोष कुमार सिंह (आई. ओ.)

अ.सा.-7 अर्थात्, प्रमोद कुमार पासवान (ब्रज प्रभारी पुलिस लाइन)

7. अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान अपने मामले को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए और उन पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं:

प्रदर्शित सं.	दस्तावेजों की सूची
प्रदर्श-1	द.प्र.स. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान ।
प्रदर्श-1/1	द.प्र.स. की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान पर हस्ताक्षर।
प्रदर्श-2	पीड़िता की आयु निर्धारण रिपोर्ट।
प्रदर्श-2/2	पीड़िता के आयु निर्धारण रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर।
प्रदर्श-3	लिखित शिकायत।
प्रदर्श-3/1	अपनी लिखित शिकायत पर सूचक के अंगूठे का निशान।
प्रदर्श-4	गिरफ्तारी ज्ञापन।
प्रदर्श-5	औपचारिक प्राथमिकी।

8. अभियोजन पक्ष के गवाहों की जाँच के बाद और मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों और आपत्तिजनक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/अपीलकर्ता का बयान 23.03.2022 को द.प्र.स. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया जिसे अपीलकर्ता ने अपनी पूर्ण निर्दोषता और झूठे आरोप का दावा करते हुए पूरी तरह से नकार दिया।

9. मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/दोषी को उपरोक्त शर्तों के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। जिससे व्यथित होकर, यह अपील प्रस्तुत की गई।

10. इसलिए, वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता/दोषी की ओर से प्रस्तुतीकरण

11. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार सिंह ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुख्यतः दो मुख्य कारणों से वर्तमान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का निर्णय रद्द/निरस्त किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में, यह प्रस्तुत किया गया कि, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता को पोक्सो अधिनियम की धारा 2(i)(डी) के अर्थ में 'बच्ची' साबित नहीं किया जा सका क्योंकि उसकी जन्म तिथि के समर्थन में एकमात्र दस्तावेज़ चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट थी अर्थात् प्रदर्श '2' जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 15 से 16 वर्ष के बीच दर्शाई गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे आगे "जे.जे. अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 94(2) के तहत संदर्भित दस्तावेज़ के आधार पर 'बच्चा' घोषित नहीं किया गया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी कानूनी रिपोर्ट के माध्यम से अनुमोदित किया है, जो **जरनैल सिंह बनाम**

हरियाणा राज्य (2013) 7 एससीसी 263 में उपलब्ध है।

12. दूसरा मुद्दा, जो अपीलकर्ता/दोषी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया था, वह यह है कि घटना के संबंध में पीड़िता का बयान उत्कृष्ट गुणवत्ता का नहीं है और इसलिए, दोषसिद्धि, जैसा कि दर्ज किया गया है, किसी और पुष्टि के अभाव में रद्द की जानी चाहिए।

13. यह तर्क दिया गया है कि निस्संदेह दोषसिद्धि केवल पीड़ित की गवाही के आधार पर दर्ज की जा सकती है, लेकिन यह विश्वसनीय, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 130 के माध्यम से उपलब्ध फैसलों पर भरोसा किया और साथ ही राय संदीप @ दीपू, बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2012) 8 एससीसी 21 में रिपोर्ट किया गया पर भी भरोसा किया।

14. अपीलकर्ता/दोषी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जो रजक मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 9 एससीसी 248 में उपलब्ध है; जहाँ यह माना गया है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर आयु का निर्धारण सटीक निर्धारण नहीं माना जा सकता और दोनों ही मामलों में पर्याप्त अंतर की अनुमति दी जानी चाहिए।

15. तर्क का समापन करते हुए, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि इस मामले के जांच अधिकारी/अ.सा.-7 भी घटनास्थल स्थापित करने में विफल रहे क्योंकि उन्होंने मुकदमे के दौरान स्पष्ट रूप से यह बयान दिया था कि उन्होंने इस मामले की जांच के दौरान घटनास्थल का दौरा नहीं किया था और, इसलिए, पूर्वोक्त पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता के रूप में दोषसिद्धि का विवादित निर्णय रद्द/निरस्त किए जाने योग्य है।

16. राज्य की ओर से विद्वान स.लो.अ. श्रीमती अनीता कुमारी सिंह ने अपीलकर्ता/दोषी की अपील का विरोध करते हुए, प्रतिवेदन किया कि पीड़िता ने विशेष रूप से अपीलकर्ता के विरुद्ध बयान दी थी कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, जब वह अपने कमरे में सो रही थी। विद्वान स.लो.अ. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमे के दौरान छोटे-मोटे विरोधाभास सामने आना स्वाभाविक है और केवल इसी आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता नाबालिग प्रतीत होती है, अर्थात् घटना की तारीख को उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी और इसलिए, पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज दोषसिद्धि भी उचित है और, इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के फैसले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

17. मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया है और पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर भी विचार किया है।

18. साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, वर्तमान अपील पर विचार करते समय, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर चर्चा करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:-

19. अ.सा.-1, अर्थात् पीड़िता, जो इस घटना की सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, ने मुकदमे के दौरान बयान दी और घटना की व्याख्या करते हुए बताया कि "छठ पूजा" के दिन जब वह सुबह-सुबह अपने कमरे में सो रही थी, अपीलकर्ता उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी बयान दी कि उसे उसके घर से बहुत दूर ले जाया गया जहाँ उसके साथ बलात्कार भी किया गया। यह भी स्पष्ट रूप से बयान दी गई कि पुलिस ने उसका पता लगा लिया था और उसके बाद उसे उसके घर वापस लाया गया। उसने बयान दी कि जब उसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले जाया जा रहा था, तब किसी ने उसे नहीं

देखा था। उसने बयान दी कि उसे अपीलकर्ता सहित दो व्यक्तियों ने अगवा किया था, जिन्होंने उसे वन क्षेत्र (जंगल) में रखा था। यह भी बयान दी गई कि अपीलकर्ता ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचीं और वीडियो बनाए और उक्त तस्वीरें और वीडियो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए। यह बयान दी गई कि अपीलकर्ता ने अपनी कैद के दौरान कई बार बलात्कार किया। यह बताया गया कि उसका बयान द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत अदालत के समक्ष दर्ज किया गया था, जिसकी उसने पहचान की थी और उसे प्रदर्श '1' के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उसने वहाँ अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की थी, जो प्रदर्श '1/1' के रूप में प्रदर्शित किए गए थे। उसने अपनी आयु निर्धारण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट पर भी अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान पर, प्रदर्श '2' के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जहां उनके हस्ताक्षर प्रदर्श 2/1 के रूप में प्रदर्शित किए गए थे।

19.1. प्रति-परिक्षण के दौरान, उसने कहा कि वह घटना से पहले अपीलकर्ता से परिचित नहीं थी। उसने अपीलकर्ता के साथ किसी भी प्रेम संबंध से भी इनकार किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय वह अपने घर में काम कर रही थी, जब अपीलकर्ता उसके घर में घुसा। घर का दरवाजा खुला हुआ बताया गया। यह भी कहा गया कि घटना के समय उसके माता-पिता "छठ घाट" पर थे। घटना रात के 3:00 बजे हुई। यह भी कहा गया कि अपहरण के समय वह बेहोश थी। यह भी कहा गया कि अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि प्रदीप श्रीवास्तव (अपीलकर्ता) था। उसने इस बात से इनकार किया कि वह प्रेम संबंधों के कारण अपीलकर्ता के साथ गई थी। उसे 13 मई, 2022 को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहाँ उसने अपीलकर्ता की पहचान उसी व्यक्ति के रूप में की जिसने उसका अपहरण किया था और उसके साथ बलात्कार किया था। प्रति-परिक्षण में कहा गया कि वह प्रदीप श्रीवास्तव को घटना के बाद ही जान पाई थी।

20. अ.सा.-2 उमेश पासवान हैं, जो पीड़िता/एक्स/अ.सा.-1 के पिता हैं और वर्तमान घटना के सूचक भी हैं। उन्होंने यह बयान दिया कि घटना के समय, पीड़िता घर पर काम कर रही थी और उसी समय अपीलकर्ता उनके घर में घुस आया और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद शोर मच गया और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता ने पीड़िता पर हमला करने और उसे मोटरसाइकिल से बांधने के बाद उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद, उन्होंने यह भी बयान दिया कि पीड़िता को चाकू की नोक पर धमकाया गया था। उन्हें ये सभी तथ्य पीड़िता के मुंह से ही पता चले। उन्होंने यह भी बयान दिया कि अपीलकर्ता ने पीड़िता को मोतिहारी स्टेशन पर छोड़ दिया और भाग गया। उन्होंने यह भी बयान दिया कि मामला देरी से दर्ज किया गया ताकि उनका समय और पुलिस अत्याचार दोनों से बच सकें। उन्होंने यह भी बयान दिया कि शुरुआत में अपीलकर्ता ने आपत्तिजनक तस्वीरें अपने पड़ोसी को भेजीं और बाद में उन्हें भेजी गईं, उसके बाद ही वह वर्तमान मामला दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने अपनी लिखित शिकायत पर अपने अंगूठे के निशान की पहचान की, जिसे उनकी पहचान के बाद प्रदर्श '3' के रूप में प्रदर्शित किया गया और उनके अंगूठे के निशान को भी प्रदर्श 3/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह बयान दिया गया कि पीड़िता का मोतिहारी के सदर अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उसका बयान भी अदालत में दर्ज किया गया। उन्होंने अपीलकर्ता की पहचान करने का दावा किया।

20.1. प्रति-परिक्षण के दौरान, उसने बताया कि वह अपहरण की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। उसे सुबह 6:00 बजे पता चला कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। उसने दावा किया कि उसने अगले 2 से 3 दिनों तक खुद खोजबीन की और उसके बाद, उसे पता चला कि घटना के दिन अपीलकर्ता उसके घर/घटनास्थल के आसपास घूमता हुआ पाया गया था और उसके बाद, वह अपीलकर्ता के घर गया, जहाँ उसने अपीलकर्ता को लापता पाया। उसने आगे बयान दी कि उसने अपनी बेटी की आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने के बाद ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी। उसे यह नहीं पता कि ये तस्वीरें पहली बार कब भेजी

गई। उसे अपनी बेटी की वायरल तस्वीरों के बारे में अपनी भाभी से पता चला। उन्होंने पुलिस के समक्ष घटना के संबंध में कोई *सनहा* (द.प्र.स. की धारा 39 के तहत सूचनात्मक याचिका) दर्ज नहीं कराई। उन्होंने झूठे आरोप लगाने के सुझाव से इनकार किया।

21. अ.सा.-3 मनोरमा देवी हैं। वह पीड़िता की माँ हैं और अ.सा.-4 रमेश राम हैं, जो सूचक/अ.सा.-2 के पड़ोसी हैं। ये दोनों गवाह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं और उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कही है, इसलिए उनकी गवाही इतनी प्रासंगिक नहीं लगती कि संबंधित अपराध पर चर्चा की जा सके। हालाँकि, अ.सा.-3 ने बयान दी कि उसने अपनी बेटी की नग्न तस्वीरें मोबाइल पर देखी थीं और पुलिस ने उसकी बेटी को बरामद कर लिया था। उसने बयान दी कि घटना के बाद वह अपनी बेटी से पहली बार पुलिस स्टेशन में मिली थी, और उसके बाद, वह उसके साथ ही रही। उसने बताया कि वह द.प्र.स. की धारा 164 के तहत अपनी बेटी का बयान दर्ज होने की तारीख को अदालत परिसर में मौजूद थी।

22. अ.सा.-5 डॉ. मनोज कुमार हैं। वे मोतिहारी के सदर अस्पताल में उपाधीक्षक के पद पर तैनात थे। उन्होंने 8 मार्च, 2022 को पीड़िता/X की जाँच की। पीड़िता की चिकित्सा जाँच के प्रासंगिक अंश को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

“पीड़िता की जाँच करने पर, मेडिकल बोर्ड ने पाया कि पीड़िता की उम्र 15-16 वर्ष है। उम्र निर्धारण परीक्षण पीड़िता/लड़की की एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि पीड़िता ने मेरी उपस्थिति में तत्काल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं।”

22.1. प्रति-परिक्षण के दौरान, उन्होंने कहा कि "यह सही है कि पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के उद्देश्य से ली गई एक्स-रे प्लेट पुलिस/आई.ओ. को नहीं सौंपी गई थी।"

23. अ.सा.-6 संतोष कुमार सिंह हैं। वे इस मामले के द्वितीय जाँच अधिकारी थे। उन्होंने ही अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 365, और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और एससी/एसटी (पी.ओ.ए) अधिनियम की धारा 3(i)(डब्ल्यू) के अंतर्गत दिनांक 27.02.202 को आरोप पत्र संख्या 21/20 प्रस्तुत किया था। प्रति-परिक्षण में, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच नहीं की थी।

24. अ.सा.-7 प्रमोद कुमार पासवान हैं। वे इस मामले के जांच अधिकारी हैं और उन्होंने बयान दी है कि वे जांच के दौरान घटनास्थल यानी अ.सा.-2/पीड़िता के घर गए थे। उन्होंने पीड़िता को अदालत में भी पेश किया, द.प्र.स. की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने के लिए। यह बयान दिया गया कि मेडिकल जांच के अनुसार, पीड़िता की उम्र 15-16 वर्ष के बीच पाई गई। इसके बाद, उन्होंने पीड़िता को उसके माता-पिता को सौंप दिया। उसने अपीलकर्ता के गिरफ्तारी जापन पर हस्ताक्षर की भी पहचान की, जो उसकी पहचान पर प्रदर्श '4' के रूप में प्रदर्शित किया गया।।

24.1. प्रति-परिक्षण के दौरान, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपीलकर्ता को 22.12.2019 को गिरफ्तार किया था और जब उन्होंने अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया, उस समय पीड़िता वहाँ मौजूद नहीं थी। अपीलकर्ता की गिरफ्तारी से पहले ही पीड़िता को बरामद कर लिया गया था। उन्होंने पुष्टि की कि जाँच के दौरान, उन्होंने सूचना देने वाले से कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं माँगा। उन्होंने मामले की जाँच के लिए, इस मामले का प्रभार प्राप्त करने के तुरंत बाद, उसी दिन घटनास्थल का दौरा किया था।

25. उपरोक्त चर्चा किए गए साक्ष्यों की पृष्ठभूमि में, अब इस मामले में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह तय करना है कि क्या अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान पीड़िता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के अर्थ में 'बच्चा' साबित किया है या नहीं।

26. इस पहलू में, यह उचित होगा कि जे. जे.अधिनियम की धारा 94 को

पुनः प्रस्तुत किया जाए, जो इस प्रकार है तत्काल संदर्भ के लिए:

“94. आयु का अनुमान और निर्धारण-

(1) जहाँ समिति या बोर्ड को, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) यह स्पष्ट हो कि उक्त व्यक्ति बच्चा है, समिति या बोर्ड बच्चे की यथासंभव लगभग आयु बताते हुए ऐसी टिप्पणी दर्ज करेगा और आयु की आगे पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 14 या धारा 36, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत जाँच शुरू करेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके, आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा, -

(i) स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और इसके अभाव में;

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर किया गया ऐसा आयु निर्धारण परीक्षण ऐसे आदेश की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।”

27. इसके अलावा, **जरनैल सिंह मामले (उपरोक्त)** के माध्यम से उपलब्ध

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 22 और 23 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

“22. नाबालिग की आयु निर्धारण के मुद्दे पर, केवल किशोर न्याय

(बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 का संदर्भ लेना आवश्यक है (जो आगे "2007 नियम" के रूप में संदर्भित)। पूर्वोक्त 2007 नियम किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68(1) के अंतर्गत बनाए गए हैं। ऊपर उल्लिखित नियम 12 इस प्रकार है:

"12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया —(1) विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति, ऐसे किशोर या बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु का निर्धारण, उस प्रयोजन के लिए आवेदन करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर करेगी।

(2) न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, किशोर या बच्चा या, जैसा भी मामला हो, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की किशोर अवस्था या अन्यथाता का निर्णय, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हों, के आधार पर करेगी और उसे अवलोकन गृह या जेल भेज देगी।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चा या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी -

(क) (i) मेट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जहाँ पहली बार शिक्षा प्राप्त की हो; और उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(ख) और केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, चिकित्सीय राय एक विधिवत् गठित मेडिकल बोर्ड से ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझे, तो बच्चे या किशोर को उसकी

आयु को एक वर्ष की सीमा के भीतर कम मानकर लाभ दे सकती है, और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सीय राय को ध्यान में रखते हुए, उसकी आयु के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करेगी और खंड (क)(i), (ii), (iii) में से किसी में निर्दिष्ट साक्ष्य या उसके अभाव में, खंड (ख) ऐसे बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में आयु का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि किसी किशोर या बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु अपराध की तिथि को 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक प्रमाण के आधार पर, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनार्थ आयु बताते हुए और किशोर होने की स्थिति घोषित करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगी या अन्यथा, और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) सिवाय इसके कि जहाँ आगे की जाँच या अन्यथा आवश्यक हो, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 7-ए, धारा 64 और इन नियमों के अनुसार, इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की जाँच और प्राप्ति के बाद न्यायालय या बोर्ड द्वारा आगे कोई जाँच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन मामलों पर भी लागू होंगे, जिनमें किशोर की स्थिति उप-नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान आवश्यक है।"

23. यद्यपि नियम 12 केवल विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए ही सख्ती से लागू होता है, हमारा यह विचार है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधान आयु निर्धारित करने का आधार होना चाहिए, यहाँ तक कि उस बच्चे के लिए भी जो अपराध का शिकार है। क्योंकि, हमारे विचार में, जहाँ तक अल्पसंख्यक होने का प्रश्न है, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे और अपराध का शिकार बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है। इसलिए, हमारी

सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष पी.सा.-अ.सा.6 की आयु निर्धारित करने के लिए 2007 के नियमों के नियम 12 को लागू करना उचित और उपयुक्त होगा। आयु का निर्णायक रूप से निर्धारण करने का तरीका, नियम 12 के उप-नियम (3) में व्यक्त किया गया है, जिसका उद्धरण ऊपर दिया गया है। उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत, नियम 12(3) में निर्धारित अधिवक्ताओं में से, प्रथम उपलब्ध आधार को अपनाकर, बच्चे की आयु का निर्धारण किया जाता है। यदि नियम 12(3) के अंतर्गत अधिवक्ताओं की योजना में, कोई अधिवक्ता पूर्ववर्ती खंड में व्यक्त किया गया है, तो उसका प्रभाव उत्तरवर्ती खंड में व्यक्त अधिवक्ता पर अध्यारोही होता है। उपलब्ध सर्वोच्च मूल्यांकन वाला अधिवक्ता, निर्णायक रूप से नाबालिग की आयु निर्धारित करेगा। नियम 12(3) की योजना में, संबंधित बच्चे का मैट्रिक (या समकक्ष) प्रमाण पत्र, सर्वोच्च मूल्यांकन वाला अधिवक्ता है। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में, नियम 12(3), बच्चे द्वारा पहली बार पढ़े गए स्कूल में दर्ज की गई जन्मतिथि पर विचार करने की परिकल्पना करता है। यदि जन्मतिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्मतिथि को अंतिम और निर्णायक माना जाएगा, और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जाएगा। केवल ऐसी प्रविष्टि के अभाव में, नियम 12(3) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा करने की परिकल्पना करता है। फिर भी, यदि ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए किसी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाणपत्र ही बच्चे की आयु का निर्णायक निर्धारण करेगा। केवल उपरोक्त में से किसी के अभाव में ही, नियम 12(3) संबंधित बच्चे की आयु का निर्धारण चिकित्सा राय के आधार पर करता है।”

28. इस मामले के तथ्यों पर गौर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता की उम्र एफआईआर में सूचक/अ.सा.-2, जो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है, द्वारा 12 वर्ष बताई गई थी। पीड़िता को घटना के लगभग 10 दिन बाद बरामद किया गया और उसके बाद द.प्र.स. की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, वहां उसकी उम्र 16 वर्ष बताई गई। पीड़िता के पास जे.जे. अधिनियम की धारा 94(2) के तहत मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या

पहले स्कूल से प्राप्त कोई प्रमाणपत्र नहीं है। स्थानीय नगर पालिका से भी पीड़िता की जन्मतिथि बताने वाला कोई प्रमाणपत्र नहीं है। पीड़िता की उम्र का निर्धारण रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर करना ही एकमात्र अधिवक्तृप बचा था। अ.सा.-5 के बयान और प्रदर्श '2', जो कि पीड़िता की उम्र का पता लगाने वाली मेडिकल रिपोर्ट है, से ऐसा प्रतीत होता है, कि उसकी उम्र 15 से 16 वर्ष के बीच है।

29. यह स्थापित कानून है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर निर्धारित आयु को कानूनी रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, रजक मोहम्मद (उपरोक्त) के मामले के माध्यम से उपलब्ध, इसलिए, यदि पीड़िता की आयु का आकलन दोनों पक्षों में दो वर्ष (+/-) जोड़कर किया जाता है, तो उस स्थिति में, पीड़िता घटना की तिथि को बालिग प्रतीत होती है। अभिलेखों के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर आयु निर्धारित करने का आधार, अर्थात् एक्स-रे रिपोर्ट और अन्य संबद्ध सामग्री, मुकदमे के दौरान उचित रूप से प्रदर्शित नहीं की गई थी।

30. इन सभी पृष्ठभूमियों को देखते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष पीड़िता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के अर्थ में 'बच्चा' साबित नहीं कर सका और, इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है और, इसलिए, अधिनियम के तहत उपलब्ध अनुमान, जैसा कि धारा 29 और 30 के तहत उपलब्ध है, वर्तमान मामले में कोई महत्व नहीं रखता है।

31. जहाँ तक दूसरे मुद्दे का सवाल है, जो अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उठाया गया था, कि क्या पीड़िता ने मुकदमे के दौरान उत्कृष्ट गवाहों की कानूनी कार्यवाही उत्तीर्ण की है ताकि आईपीसी की धारा 376 या प्रवेशन लैंगिक हमले के तहत दोषसिद्धि उसकी एकमात्र गवाही पर विश्वास की जा सके।

32. उपरोक्त संदर्भ में, पीड़िता के पहले बयान पर चर्चा करना उचित होगा जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, अर्थात् द.प्र.स. की धारा 164 के तहत दर्ज उसका बयान। उसके बयान से पता चलता है कि जब वह 'छठ पूजा' के अवसर पर सुबह लगभग 5:00 बजे अपने घर में खाना बना रही थी, तो अपीलकर्ता उसके घर में घुस आया और उसे 'ओढ़नी' से बांधकर बेहोश कर दिया, उसके बाद उसका अपहरण कर लिया। जब वह होश में आई, तो उसने खुद को जंगल में पाया। उसने अपीलकर्ता से घर वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन चाकू की नोक पर उसने कई आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं और वीडियो भी बनाए, जिन्हें वायरल कर दिया गया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता ने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसने तस्वीरें देखने का भी दावा किया। उसने बताया कि वह अपीलकर्ता के साथ सीतामढ़ी गई थी, जहाँ वह अपनी मौसी के साथ थी।

33. अब उसकी बयान पर आते हैं, जैसा कि उसने मुकदमे के दौरान अ.सा.-1 के रूप में दिया था, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि घटना की तारीख को वह अपने कमरे में सो रही थी जब अपीलकर्ता वहाँ घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने बताया कि उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि प्रति-परिक्षण में उसने फिर से कहा कि वह घटना के समय यानी लगभग 3:00 बजे अपने घर में काम कर रही थी। उसके उपरोक्त दो बयानों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने यौन उत्पीड़न/बलात्कार के आरोप का खंडन किया। उसने घटना का अलग समय भी बताया। उसने पहली बार मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष अपने साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। ऐसी सभी बड़ी विसंगतियों और विविधताओं को देखते हुए, उसे प्रथम दृष्टया 'उत्कृष्ट गवाह' के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए, बाकी सबूतों से आरोप की और पुष्टि आवश्यक है। अब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा '22' को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जैसा कि राय संदीप @ दीपू (उपरोक्त) के मामले के माध्यम से उपलब्ध है, जो इस प्रकार है:

“22. हमारी सुविचारित राय में, “उत्कृष्ट गवाह” बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, इसलिए, जिसका कथन, अकाट्य होना चाहिए। अदालत ऐसे गवाह के बयान पर विचार करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होनी चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और जो प्रासंगिक होगा वह है ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सत्यता। अधिक प्रासंगिक बात यह होगी कि बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष, एकरूपता बनी रहे। अभियुक्त के रूप में यह स्वाभाविक और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के बयान में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। गवाह किसी भी लंबाई और कितनी भी कठिन प्रति-परीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश न छोड़ें। इस तरह के विवरण का अन्य सभी सहायक सामग्री जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सहसंबंध होना चाहिए। उक्त विवरण हर दूसरे गवाह के विवरण से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध का दोषी ठहराए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी परीक्षणों को भी पूरा करता हो, तभी यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को “उत्कृष्ट गवाह” कहा जा सकता है, जिसका बयान अदालत बिना किसी पुष्टि के स्वीकार कर सकती है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो, अपराध के मूल पहलू पर उक्त गवाह का बयान बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी संबंधित सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएँ, उक्त बयान से भौतिक विवरणों में मेल खानी चाहिए ताकि अपराध की सुनवाई कर रही अदालत अन्य सहायक सामग्रियों को छांटने के लिए मूल बयान पर भरोसा कर सके और कथित आरोप के लिए अपराधी को दोषी ठहरा

सके।”

34. पीड़िता को 'उत्कृष्ट गवाह' मानने पर संदेह करने के बाद, इस संदर्भ में पहला और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य है। अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इस मामले में केवल डॉक्टर, अ.सा.-5, अर्थात् डॉ. मनोज कुमार जिन्होंने इस मामले की जांच की, जिन्होंने केवल पीड़िता की उम्र के बारे में बताया, जहाँ उन्होंने पाया कि पीड़िता की उम्र 15 से 16 वर्ष के बीच है, सिवाय इसके कि, पूरी जाँच में यौन उत्पीड़न/शारीरिक उत्पीड़न के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जिससे यह संदेह होता है कि क्या पीड़िता पर कोई यौन उत्पीड़न किया गया था। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पीड़िता की चोट की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में नहीं लाई गई, जबकि उसकी सदर अस्पताल, मोतिहारी में चिकित्सीय जाँच की गई थी।

35. अ.सा.-2, जो कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का पिता है, का बयान भी संबंधित अपराध के रूप में चर्चा के लिए प्रासंगिक है जहाँ तक पीड़िता के अपहरण का संबंध है, जो वर्तमान घटना का मूल कारण है। उसके बयान से यह प्रतीत होता है कि घटना उस समय हुई जब पीड़िता "छठ घाट" पर आ रही थी। यदि उसके बयान को ध्यान में रखा जाए, तो उसे पीड़िता के मुँह से जो पता चला, जैसा कि उसने बयान दिया था, उसे ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से अपहरण की घटना "छठ घाट" के रास्ते में हुई थी और इस प्रकार, अपहरण के संबंध में भी एक गंभीर संदेह पैदा होता है जैसा कि पीड़िता ने पहले स्वयं कहा था। प्राथमिकी/प्रदर्श-3, जो एक लिखित शिकायत/सूचना है, से यह भी प्रकट होता है कि पीड़िता को अपीलकर्ता ने "छट्टी माई" (स्थान का नाम) पर छोड़ा था, जबकि मुकदमे के दौरान, उसने यह बयान दिया था कि पीड़िता को अपीलकर्ता ने मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था।

36. अ.सा.-1/पीड़िता के बयान पर दोबारा आते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि

उसे अपीलकर्ता ने न तो "छठ माई" पर छोड़ा था और न ही "मोतिहारी रेलवे स्टेशन" पर, बल्कि उसे पुलिस ने बरामद किया था। पीड़िता के अपहरण और उसकी बरामदगी का पूरा विवरण घटना के संबंध में गंभीर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्राथमिकी पीड़िता की बरामदगी के 15 दिन बाद और कुल मिलाकर घटना के 25 दिन बाद दर्ज की गई थी। अ.सा.-2 द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि पुलिस के अत्याचार और समय की बचत के लिए, प्राथमिकी तुरंत दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन यह स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं लग रहा है। अपीलकर्ता ने, द.प्र.स. की धारा 313 के तहत अपनी परीक्षा के दौरान विशिष्ट प्रश्नों पर, कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया था क्योंकि कथित घटना से 2-3 दिन पहले, उसके पिता और पीड़िता के पिता के बीच झगड़ा हुआ था और, इसलिए, उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया था। घटना के 25 दिन बाद वर्तमान प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का अविश्वसनीय स्पष्टीकरण, बाद में विचार करने के लिए पर्याप्त समय-अंतराल देता है।

37. अतः वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

38. तदनुसार, तुरकौलिया (बंजरिया) थाना मामला संख्या 850/2019 से उद्भूत पी.टी.आर. संख्या 14/2020 के संबंध में विद्वान छठे सहायक सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा पारित दिनांक 28.01.2023 का दोषसिद्धि निर्णय और दिनांक 09.02.2023 का सजा आदेश निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता, अर्थात् प्रदीप श्रीवास्तव, को विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

39. चूँकि अपीलकर्ता उपरोक्त मामले के संबंध में हिरासत में है, इसलिए उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो। यदि कोई जुर्माना जमा किया गया हो, तो उसे तत्काल अपीलकर्ता को वापस कर

दिया जाए।

40. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह बिना किसी देरी के, इस निर्णय को विचारण न्यायालय अभिलेखों (टीसीआर) के साथ एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेज दे।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।